मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों की एसी ट्रेन को रामेश्वरम, मदुरई रवाना किया

उन्होंने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 25-26 का शुभांरभ किया

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल 50 हजार वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेनों से 13 तीर्थस्थलों की यात्रा करायेगी।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की प्रथम वातानुकूलित ''राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन'' को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनको सुगम एवं सफल यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

जयपुर, 6 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही, योजना के तहत प्रथम वातानुकूलित 'राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस एसी ट्रेन से वरिष्ठ नागरिकगण रामेश्वरम एवं मदुरई के तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनकी सुगम एवं सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठजन हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर और समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनके अनुभव और आदर्श हमें जीवन में सही राह पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जीवन भर समाज एवं राष्ट्र की सेवा करने वाले वरिष्ठ जनों की सेवा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भाव है।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के मन में यह इच्छा रहती है कि वह अपने जीवनकाल में महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों की यात्रा करे, वरिष्ठजनों की पावन धामों के दर्शन करने की इच्छा से प्रेरित होकर यह तीर्थयात्रा योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान सभी तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा भोजन, ठहरने की सुविधा सहित, सभी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत, इस साल 50 हजार वरिष्ठजनों को पहली बार एसी ट्रेनों से 13 विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। इसके पहले लगभग छह हजार श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए गए हैं। इस अवसर पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद मदन राठौड़, मंजू शर्मा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और उनके परिजन उपस्थित थे।

जी-7 की मीटिंग के लिए मोदी को न्यौता

नयी दिल्ली, 06 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी-7 देशों की शिखर बैठक में शामिल होने इस महीने कनाडा जायेंगे। यह बैठक 15 से 17 जून तक अलबर्टा प्रांत के कनानास्किस में होनी है।

मोदी ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी ने उन्हें फोन कर जी -7 की बैठक का न्यौता दिया। उनकी इस पोस्ट से पिछले कुछ दिनों से भारत के इस बैठक में शामिल होने को लेकर लगायी जा रही अटकलों पर विराम लग गया है।

- **प्र.मंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि कैनडा के प्रधानमंत्री ने फोन करके जी-7 मीटिंग में आने का निमंत्रण दिया है।**

मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री मार्क जे कानी का फोन आने पर प्रसन्नता हुई। मैंने उन्हें हाल के चुनावों में मिली विजय के लिए बधाई दी और कनानास्किस में इस महीने होने वाली जी-7 की बैठक में भाग लेने का आमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया।

जी-7 देशों में कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन तथा इटली शामिल हैं। मोदी इस शिखर बैठक में विशेष आमंत्रित के तौर पर भाग लेंगे।

सचिन पायलट ने टोंक के 10 गाँवों में जनसुनवाई की

मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार केवल धुआं फेंक रही है

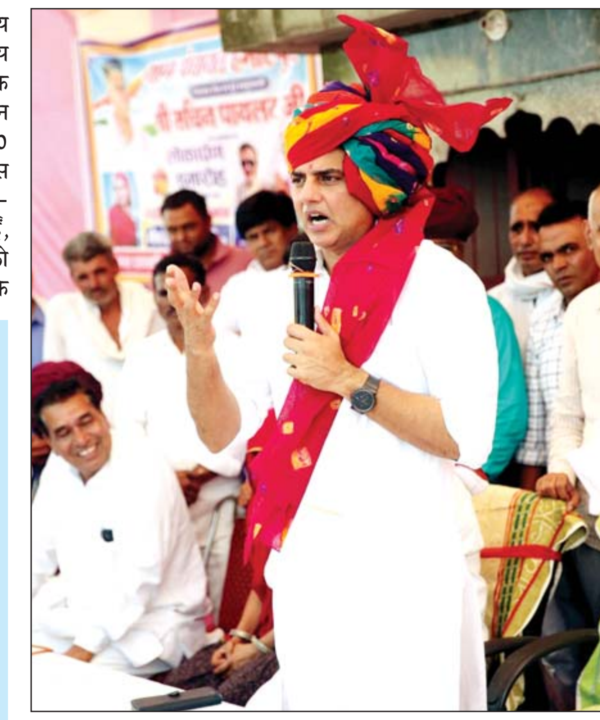

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने टोंक दौरे के दूसरे दिन करीब 10 गांवों का दौरा कर जनसुनवाई की।

टोंक, 6 जून (निस)। दो दिवसीय दौरे पर आये कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने दूसरे दिन टोंक विधानसभा क्षेत्र के करीब 10 गांवों का दौरा कर जनसुनवाई की। इस दौरान लोगों ने पायलट को बिजली-पानी सहित कई परेशानियां बताईं, जिसके लिए पायलट ने अधिकारियों को निर्देश देकर जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

- **कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पायलट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 11 बार कहा कि व्यापार का लालच देकर सीज़फायर कराया। यह दुख की बात है, अभी तक सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों ने इसका खंडन नहीं किया।**

पायलट ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही है। भाजपा के पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल से लग रहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार में किये गये कार्यों की देखरेख भी वर्तमान भाजपा सरकार ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के आकाओं को खुश करने में लगा हुआ है।

पायलट ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार नहीं, 11 बार यह कहा कि व्यापार का लालच देकर सीज़ फायर करवाया है। यह बड़े दुख की बात है कि अभी तक भी सर्वोच्च पद पर बैठे जिम्मेदार लोगों ने इसका खंडन नहीं किया है, वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होते हैं सीज़ फायर करवाने वाले। पायलट ने कहा कि जवाबी कार्यवाही तो उसे कहते हैं, जब इंदिरा गांधी के समय पाकिस्तान के 95 हजार सैनिकों ने हथियार डाल दिये थे। पाकिस्तान में टूटी- फूटी सरकार है।

पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत और गुर्जर आरक्षण को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि संविधान में जो राहत लोगों को दी गई है, उस पर अमल नहीं होगा तो जनता को उसका जवाब मांगने का अधिकार है। जो एग्रीमेंट हैं, गजट नोटिफिकेशन हैं, उनकी पालना नहीं होती हैं, यह तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए।

पायलट के दौरे के दौरान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, भंवर लाल बंशीवाल सहित, सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे।

मोदी सरकार की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर चिंता बढ़ा दी है।

शीर्षस्थ कूटनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञ भारत की रणनीतिक स्थिति को कमज़ोर होते देख कर चिन्तित एवं आशंकित दिखाई दे रहे हैं। एक पूर्व भारतीय राजदूत ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, " गहन प्रयासों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में पाकिस्तान की भूमिका को रोकने में भारत की असफलता यह दर्शा रही है कि विदेश नीति में इरादे और अमल के बीच गहरी खाई है।

पूर्व विदेश मंत्री और मोदी सरकार की विदेश नीति व आर्थिक नीति के प्रखर आलोचक डॉ. के.सी. मेनन ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "भारत की वैश्विक साख पर गंभीर अविश्वास खड़ा हो रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नतीजों का सामना किए बिना, अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी।"

लेकिन सरकार ने इन आरोपों पर घोर चुप्पी साध ली है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बस इतना कहा कि एक दीर्घकालिक कूटनीतिक रणनीति चल रही है और अल्पकालीन महत्व की घटनाएं भारत की वास्तविक वैश्विक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करतीं।"

इस बीच, विपक्षी गठबंधन "इंडिया" आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति के रंग-ढंग को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुये एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी में है। वरिष्ठ नेताओं ने सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में पारदर्शिता और जम्मू-कश्मीर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति से निपटने की योजना को स्पष्ट करने की मांग की है।

जैसे-जैसे संसद का मानसून सत्र नज़दीक आ रहा है, तीखे राजनीतिक टकराव का मंच तैयार हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार अपनी (विजय) गाथा पर अड़ी रहेगी तथा उसे ही दोहराती रहेगी या फिर उसे देश और दुनिया में अपनी विदेश नीति की दिशा पर बढ़ती चिंता का सामना करना पड़ेगा।

'जम्मू-कश्मीर में बना विकास का माहौल, पहलगाम हमले से नहीं रुकेगा'

प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ऊँचे चिनाब रेल ब्रिज के उद्घाटन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा

श्रीनगर, 06 जून। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार जम्मू-कश्मीर दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने चिनाब ब्रिज का जायजा भी लिया और इसको बनाने वाले कामगारों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने इसी ट्रैक पर बने अंजी ब्रिज का भी लोकार्पण किया। ये देश का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है, जो केबल स्टेड तकनीक पर बना है। यह ऐतिहासिक पुल न सिर्फ कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, बल्कि क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के जरिये जम्मू से श्रीनगर का रास्ता केवल 3 घंटे का रह जाएगा।

पीएम मोदी ने आज जम्मू-कश्मीर में 46 हजार करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया।

मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और कश्मीर के टूरिज्म का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला था। यह पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी, जो कश्मीर में तेजी से बढ़ रहे पर्यटन और आर्थिक विकास को रोकना चाहता था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के वेग को रुकने नहीं दिया जाएगा।

- **प्रधानमंत्री ने इसी ट्रैक पर बने अंजी ब्रिज का भी लोकार्पण किया। यह देश का पहला ऐसा ब्रिज है जो केबल स्टैंड तकनीक पर बना है।**
- **मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत व कश्मीरियत पर हमला किया, वे भारत में दंगे कराना चाहते थे, पर, कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया।**

प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले में नौजवान आदिल की हत्या का भी उल्लेख किया और कहा कि आदिल वहां मेहनत-मजदूरी करने गया था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू-कश्मीर की आवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनियाभर की आतंकवादी मानसिकता को, जम्मू-कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है।

उन्होंने कहा कि विकास का जो वातावरण जम्मू-कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गत 06 मई की वो रात, पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा, तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। सभा में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जितेन्द्र सिंह और वी सोमन्ना जी, जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेन्द्र कुमार, विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील और अन्य गणमान्य व्यक्त उपस्थित थे।

क्या ''इमरजैंसी'' ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया है। इसके विपरीत, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस सहित 16 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि ऑपरेशन 'सिंदूर' और उससे जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। सरकार ने न तो इमरजेंसी सत्र को लेकर कांग्रेस के दावे पर कोई प्रतिक्रिया दी है, न ही इंडिया ब्लॉक के विशेष सत्र के अनुरोध पर कोई जवाब दिया है। ऐसे में स्थिति अभी भी गतिशील बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक सरकार की ओर से किसी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, ताकि विशेष संसद सत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।

'अपराध गंभीर हो तो एंटीसिपेटरी बेल ना दें'

नई दिल्ली, 6 जून। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंभीर अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी पूर्व जमानत बिना सोचे-समझे नहीं दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने यह टिप्पणी बिहार के एक हत्या के मामले में चार आरोपियों को दी गई गिरफ्तारी पूर्व जमानत रद्द करते हुए की।

पीठ ने 1 मई को दिए गए आदेश में कहा, पटना हाईकोर्ट का आदेश बिना किसी ठोस वजह के दिया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या की

- **सुप्रीम कोर्ट ने यह लैंड मॉर्क टिप्पणी पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। पटना हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डालने के आरोपियों को जमानत दे दी थी।**

कोशिश) जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, यह आदेश संक्षिप्त और न्यायिक विश्लेषण से रहित है। ऐसे गंभीर मामलों में इस तरह से स्वचालित रूप से जमानत नहीं दी जा सकती। यह आदेश रद्द किया जाना चाहिए।मामले में कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और अन्य दस्तावेजों के अनुसार, शिकायतकर्ता के पिता की उसके सामने ही लोहे की रॉड और डंडों से पिटाई की गई थी, जिससे उसकी उसी दिन मौत हो गई। यह विवाद रास्ते में रुकावट को लेकर हुआ था। एफआईआर में आरोपियों की भूमिका साफ तौर पर बताई गई है।

करोना के एक्टिव केस हुए 5 हजार के पार

नयी दिल्ली, 06 जून। देशभर में करोना संक्रमण के 464 सक्रिय मामले बढ़ने के साथ कुल सक्रिय मामलों की संख्या शुक्रवार सुबह 5364 तक पहुंच गयी। पिछले 24 घंटों में इसके संक्रमण से चार और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 55 तक पहुंच गयी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, सुबह आठ बजे तक देश में करोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ कर 5364 पहुंच गयी। अभी तक 4724 मरीजों को स्वास्थ्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है और एक जनवरी से अब तक 55 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में करोना संक्रमण के कुल 1266 मामले सामने आये हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। देश के नौ राज्यों में करोना के सक्रिय मामले सबसे अधिक हैं, जिनमें से केरल, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसी अवधि में करोना संक्रमण के 498 नये सक्रिय मामले सामने आये हैं और 764 मरीजों के स्वस्थ्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है लेकिन इस अवधि के दौरान चार और मरीजों की जान चली गयी।

भगवान सिंह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।

देवनानी ने कहा कि उनका निधन हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

वसुंधरा राजे ने कहा कि उनके निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। उन्होंने जीवनपर्यंत संगठन और समाज की सेवा को अपना धर्म माना।

इसी तरह उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं प्रेम चंद बैरवा, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित, कई नेताओं ने रोलसाबसर के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है।

कांग्रेस ने ट्रंप-मस्क की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मेल खाती रही हैं - जिनमें बंदरगाह, हवाई अड्डे, ऊर्जा, कोयला और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

वर्ष 2015 से ही भारतीय मीडिया ने इस प्रवृत्ति की ओर इशारा किया था: जहाँ भी मोदी विदेश दौरे पर जाते, उसके तुरंत बाद ही अडानी भी वहाँ एक्टिव हो जाते।

2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उसके तुरंत बाद अडानी समूह के कारोबार में तीव्र विस्तार हुआ। इस अवधि में समूह ने बंदरगाहों, हवाई अड्डों, नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा सेंटर और ऊर्जा उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की

2014 में अडानी की अनुमानित संपत्ति लगभग 3.5 अरब डॉलर थी और 2022 तक, वे थोड़े समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति तक बन गए थे।

उस समय मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान, मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए कथित रूप से अडानी के प्राइवेट जैट का इस्तेमाल किया था।

इसके अलावा, अडानी समूह ने रणनीतिक सार्वजनिक परिसंपत्तियों, जैसे छह प्रमुख हवाई अड्डों (जिसमें मुंबई भी शामिल है) और प्रमुख बंदरगाहों, मुंद्रा और विजिंजम, की निविदाएं जीतीं और उन पर नियंत्रण किया।

पिछले एक दशक में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि अडानी समूह का अंतरराष्ट्रीय विस्तार अक्सर मोदी की उच्च स्तरीय कूटनीतिक यात्राओं के साथ मेल खाता है।

कई मामलों में, मोदी की यात्राओं के बाद महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौते होते देखे गए हैं।

कांग्रेस ने इस बार एक अंतरराष्ट्रीय विवाद को बहुत चतुराई से भारतीय संदर्भ में ढाल कर मोदी-अडानी संबंधों को फिर से चुनावी विमर्श के केन्द्र में ला दिया है।

3 अगस्त को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की बजाय एक ही पाली में आयोजित कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर एनबीई परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की अनुमति के लिए गुहार लगा सकती है।

शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद एनबीई ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने समेत सुरक्षा संबंधी अन्य उपाय करने का हवाला देते हुए तीन जून को एक आवेदन के जरिए परीक्षा को तीन अगस्त को आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।

अब आर.टी.जी.एस. से पैसा ट्राँसफर लगभग सभी ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फॉर इंटरनेशनल सैटलमैंट्स) आम जनता के बीच भले ही कम जाना-पहचाना नाम हो, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर देश के पास केंद्रीय बैंक होता है जो प्राइस स्टेबिलिटी और मॉनिटरी सिस्टम की निगरानी करता है, और बी.आई.एस. एक तरह से इन केंद्रीय बैंकों का "बैंकर" है।

बी.आई.एस. ने 17 मई को स्विट्ज़रलैंड के बाज़ल शहर में अपनी 95वीं वर्षगांठ मनाई, जहाँ इस संस्था द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिकाओं को प्रदर्शित किया गया। बी.आई.एस. की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के तुरंत बाद जर्मनी से युद्ध हर्जाने के भुगतान के प्रबंधन के लिए की गई थी।

प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को युद्ध हर्जाने के रूप में भारी भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। ये भुगतान पहले बी.आई.एस. को दिए जाते थे, जो फिर फ्रांस या ब्रिटेन जैसे विभिन्न देशों के दावे निपटाता था।

लेकिन 1932 तक, वर्साय शांति समझौता और उसके हर्जाना भुगतान के प्रावधान अप्रभावी हो गए, क्योंकि जर्मनी इतनी बड़ी रकम चुकाने की स्थिति में नहीं था। जर्मनी में अत्यधिक महंगाई के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और प्रयासों के बावजूद कोई भी राशि नहीं वसूली जा सकी।

इसलिए बी.आई.एस. की मूल भूमिका अप्रासंगिक हो गई और यह धीरे-धीरे विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच लेनदेन और दावों को निपटाने का मंच बन गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बी.आई.एस. को एक नई भूमिका मिली। यह अमेरिका की मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी रकम के हस्तांतरण का प्लेटफॉर्म बन गया। जब पुनर्निर्माण कार्य धीमा पडने लगा, तो बी.आई.एस. एक ऐसा मंच बन गया जहाँ केंद्रीय बैंक अधिकारी मिलकर मौद्रिक स्थिरता और

- **पर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए भारी राशि आई, अमेरिका के मार्शल प्लान के तहत, तब बी.आई.एस. की दुकान फिर चल पड़ी।**
- **पर, कालांतर में, बी.आई.एस. को समय की आवश्यकता के अनुसार, अपना स्वरूप व कामकाज बदलना पड़ा और अब आर.टी.जी.एस. के रूप में वह पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्तीय संकटों से गुजरने के अनुभव की उसकी स्मृतियां तथा डेटा बेस उसका सबसे बड़ा ''एसैट'' (धरोहर) हैं तथा फायनैंशियल सिस्टम को संकटों से निपटने के लिए उठाये गये नीतिगत निर्णय व प्रक्रिया, अब भावी संकटों से निपटने में भारी भूमिका निभायेंगे।**

नीतियों पर चर्चा करने लगे।

केन्द्रीय बैंकों के बीच पॉलिसी पर विचार विमर्श के लिए बी.आई.एस. प्लेटफॉर्म का मुख्य आधार इसकी मजबूत शोध क्षमताएं और डेटाबेस है। बी.आई.एस. इन केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीतियों पर समन्वय स्थापित करने का प्रमुख मंच प्रदान करता है। यद्यपि प्रत्येक देश की अपनी आर्थिक परिस्थितियाँ और जरूरतें होती हैं, जिनका समन्वय करना होता है।

बी.आई.एस. की एक अन्य भूमिका यह भी रही कि यह वैश्विक स्तर पर धन प्रवाह (फ्लो ऑफ फण्ड्स) की निगरानी करे। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद विभिन्न आर्थिक और वित्तीय घटनाओं के कारण विभिन्न देशों के बीच फंड का प्रवाह बढ़ने लगा।

इसका एक प्रमुख कारण था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हटकर बाजार आधारित एक्सचेंज रेट की ओर जाना। इससे देशों की मौद्रिक नीतियों को नई दिशा में ढालना आवश्यक हो गया?

ये बदलाव उस नए वैश्विक आर्थिक माहौल का सीधा नतीजा थे, जो उस समय उभर रहा था। पहले यह माना जाता था कि किसी भी देश के करंट अकाउंट (चालू खाते) में शून्य बैलेंस होना चाहिए और किसी भी स्थिति में चालू खाता घाटा (स्ट्रक्चरल करंट एकाउंट डैफिसिट) स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन बाद में यह सोच बदलने लगी। इस नए सिस्टम का मुख्य आदर्श उदाहरण यह था कि कुछ देशों (जैसे चीन) के पास भारी मात्रा में सरप्लस पूँजी जमा होने लगी और कुछ देशों (जैसे अमेरिका) पर भारी घाटा हो गया।

इसका नतीजा यह हुआ कि दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के बीच बड़े पैमाने पर पूंजी का प्रवाह होने लगा। इससे बाजार में उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता पैदा होने लगी।

व्यापार के जरिए आने वाले पैसों के साथ-साथ, बाजार में नई ताक़त के रूप में संस्थागत निवेशक (इन्स्टिट्यूश्नल इन्वैस्टर) सामने आए। ये निवेशक सिर्फ एक बटन दबाकर बड़ी रकम को एक देश से दूसरे देश में भेज सकते थे। ऐसे अचानक आने-जाने वाले अनुमानित निवेश (स्पैक्युलेटिव फण्ड्स) से एक्सचेंज रेट्स में भारी बदलाव आ सकते थे, जो आगे चलकर देशों की असली अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते थे।

इतने बडे पैमाने पर हो रहे पैसों के आवागमन के सामने बी.आई.एस. की भुगतान और निपटारे की पारम्परिक भूमिका अब कमजोर व अप्रासंगिक हो गई।

लेकिन बी.आई.एस. के लिए एक नई भूमिका साफ दिखाई दे रही थी, इसका डेटाबेस और रिसर्च संसाधन आर्थिक संकट के समय नीति बनाने में मददगार बन सकते थे।

इस तरह, बी.आई.एस. अब अपनी मूल भूमिका से बहुत आगे निकल गया है और अब यह एक ऐसा स्थायी मंच बन गया है जहाँ दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के नीति निर्माता मिलते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी और बैंकिंग रेगुलेशन पर चर्चा करते हैं, ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रह सके।

बी.आई.एस. (बैंक फॉर इन्टरनैशनल सैटलमैंट) की स्थापना आज की आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक जैसी ब्रैट संस्थाओं से भी पहले हुई थी। यह अब ग्लोबल फायनैंस में 100 साल पूरे करने की ओर बढ़ रहा है।

बी.आई.एस. के पास वित्तीय संकटों का संस्थागत अनुभव, आर्काइव्ज़ और डेटा मौजूद हैं - जो आने वाले समय में वित्तीय पूंजीवाद (फायनैंशियल कैपिटलिज़्म8) को बनाए रखने के लिए एक अमूल्य संसाधन साबित हो सकते हैं।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालयः** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, **उदयपुर कार्यालयः** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालयः**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422,226423, फैक्सः 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908